हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

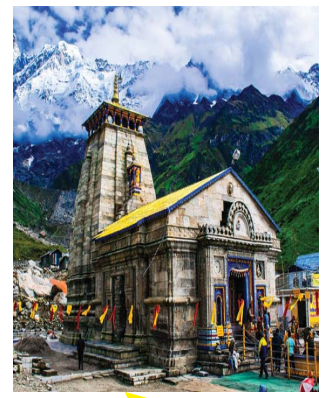

वर्ष:5 अंक:12 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

यूसीसी में अपर सचिव लेवल के अधिकारी भी बन सकेंगे रजिस्ट्रार जनरल, पहचान छिपाकर की शादी होगी अमान्य घोषित

देहरादून। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हुआ था. यूसीसी लागू होने के बाद यूसीसी नियमावली में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं. इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक बार फिर यूसीसी में संशोधन करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी यूसीसी के रजिस्ट्रार जनरल बन सकेंगे. यही नहीं, पहचान छिपाकर विवाह करने पर शादी को अमान्य घोषित किए जाने संबंधित बिंदु को भी यूसीसी में शामिल किया गया है. इसके अलावा, यूसीसी के सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दे दिया गया है.

दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान कैबिनेट ने समान

नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी है. लिहाजा यूसीसी संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा. समान नागरिक संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार, 27 जनवरी 2025 से पहले और 27 मार्च 2010 के बीच हुई शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए यूसीसी लागू होने के बाद अगले 6 महीने का समय दिया गया था. ऐसे में राज सरकार ने 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों को 6 माह के बजे एक साल में विवाह रजिस्ट्रेशन कराने प्रावधान किया है. हालांकि, इस एक साल का समय पूरा होने में अब महज 10 दिनों का ही समय बचा है. क्योंकि 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुई थी, उसके बाद एक साल का समय 26 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है.

इसके साथ ही यूसीसी में रजिस्ट्रार जनरल के लिए पहले न्यूनतम सचिव लेवल के अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान था. जिसे अब बदलकर न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी कर दिया गया है. यानी अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी भी यूसीसी के रजिस्ट्रार जनरल बन सकेंगे. इस संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. वर्तमान समय में सचिव वी षणमुगम यूसीसी में बतौर रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इस संशोधन के बाद संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी किसी अपर सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपी जा सकती है.

इसके साथ ही यूसीसी में प्रावधान था कि अगर सब रजिस्ट्रार समय से काम नहीं करते हैं तो यूसीसी नियमावली में सब रजिस्ट्रार पर फाइन लगाने का प्रावधान किया गया था. जबकि फाइन लगाने की व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही लगाया जा सकता है. जिसको देखते हुए यूसीसी नियमावली में फाइन शब्द को हटाकर उसकी जगह पेनल्टी शब्द लिखने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दे दिया गया है जबकि अभी तक ये अधिकार रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल को ही था.

यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में पहचान छिपाकर शादी करने पर उस शादी को अमान्य (Voidable) घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं था. ऐसे में नियमावली में इस बिंदु को भी शामिल कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर शादी करता है तो उस शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि, शादी को अमान्य करने की प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से होगी. लेकिन यूसीसी नियमावली में इस बिंदु को भी शामिल कर दिया गया है.

उत्तराखंड सरकार-आईटीबीपी के बीच 'स्वस्थ सीमा अभियान' एमओयू

पथ प्रवाह, देहरादून।

सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड शासन एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के बीच 'स्वस्थ सीमा अभियान' के अंतर्गत एक अहम समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, आईजी आईटीबीपी उत्तरी सीमांत संजय गुंज्याल सहित आईटीबीपी एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस एमओयू का उद्देश्य पिथौरागढ़, चमोली

और उत्तरकाशी जनपदों के 108 सीमावर्ती गांवों में निवासरत नागरिकों को एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। अभियान को प्रथम चरण के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

समझौते के तहत आईटीबीपी द्वारा योग्य चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, एमआई रूम तथा टेली-मेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीमावर्ती गांवों का नियमित भ्रमण कर स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही लाभार्थियों के मेडिकल हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड के संधारण तथा दवाइयों, उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों के समुचित प्रबंधन की जिम्मेदारी भी आईटीबीपी द्वारा निभाई जाएगी।

वहीं उत्तराखंड सरकार संबंधित गांवों के जनसांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध कराएगी और प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था करेगी। उपभोग के आधार पर प्रत्येक छह माह में दवाइयों और अन्य सामग्रियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में निकासी, दूरसंचार सहायता और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'स्वस्थ सीमा अभियान' सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रभावी और दूरदर्शी पहल है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सीमांत गांवों में विश्वास, सुरक्षा और स्थायित्व को भी मजबूत करेगा। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार और आईटीबीपी के बीच सहयोग से स्थानीय उत्पादों की खरीद, संपर्क व्यवस्था और सेवाओं के विस्तार में भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आजीविका, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिली है।

ईरान से गुजरने वाली कई भारतीय उड़ानें रद्द, अन्य के मार्ग बदले

नयी दिल्ली। भारतीय विमान सेवा कंपनियों ने ईरान के ऊपर से गुजरने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी हैं जबकि कई अन्य के मार्गों में बदलाव किया गया है।

ईरान द्वारा वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उसके हवाई क्षेत्र को बंद किये जाने के बाद यह फैसला लिया गया है।

टाटा समूह की एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि 'ईरान में बने घटनाक्रम, उसके बाद हवाई क्षेत्र बंद किये जाने और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर' उस क्षेत्र से गुजरने वाली उड़ानों के मार्ग बदले गये हैं जिससे उड़ानों में देरी हो सकती है।

भारतीय लोकतंत्र एक विशाल वृक्ष, विविधता इसकी सबसे बड़ी ताकत : पीएम मोदी

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विविधता को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा है कि भारत ने यह साबित किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं लोकतंत्र को स्थिरता, गति और व्यापक स्तर प्रदान करती हैं और इसी का परिणाम है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं तथा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत इस विविधता का उत्सव मनाता है क्योंकि लोकतंत्र की नींव मजबूत है। भारतीय लोकतंत्र एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसे गहरी जड़ें सहारा देती हैं। मोदी ने गुरुवार को यहां राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों तथा पीठासीन अधिकारियों के 28 वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सम्मेलन के मुख्य विषय 'संसदीय लोकतंत्र की प्रभावी परिणति' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी विविधता में, भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा लेकिन भारत ने इसी विविधता को लोकतंत्र की ताकत बना दिया। उन्होंने कहा कि

एक बड़ी आशंका यह भी थी कि भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा लेकिन भारत ने साबित किया कि लोकतांत्रिक संस्थान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लोकतंत्र की स्थिरता , गति और पैमाना तीनों आते हैं। भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढती अर्थव्यवस्था बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा,' हम लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में लोकतंत्र सार्थक परिणाम देता है। '

उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र से इसलिए परिणाम मिलता है क्योंकि सरकार के लिए देश की जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, ' हमने जनता की आकांक्षाओं को, जनता-जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रक्रिया से लेकर प्रौद्योगिकी तक, हर चीज का लोकतांत्रिकरण किया है और यह लोकतांत्रिक भावना हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। ' इस संदर्भ में उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चुनौतियों के बीच भारत द्वारा डेढ़ सौ से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ' लोगों का हित, लोगों की भलाई और उनका कल्याण, ये हमारा संस्कार है, और ये संस्कार हमें हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं। प्रधानमंत्री ने देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में महिलाएं केवल भागीदार ही नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका में हैं। उन्होंने कहा कि यह सशक्तिकरण आप को शीर्ष पद राष्ट्रपति से लेकर गांवों में निम्न स्तर तक दिखाई देगा। मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की विविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। विभिन्न भाषाओं में नौ सौ से अधिक टेलीविजन चैनल हैं। हजारों समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। बहुत कम समाज इतने बड़े स्तर पर विविधता का प्रबंधन कर पाते हैं। भारत इस विविधता का उत्सव मनाता है क्योंकि हमारे लोकतंत्र की नींव मजबूत है। हमारा लोकतंत्र एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसे गहरी जड़ें सहारा देती हैं। उन्होंने कहा कि यहां वाद-विवाद, संवाद और सामूहिक निर्णय-निर्माण की एक लंबी परंपरा रही है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। हमारे पवित्र ग्रंथ वेद पांच हजार वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। उनमें ऐसी सभाओं का उल्लेख है, जहां लोग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते थे।

नगर आयुक्त नंदन कुमार का चीनी मांझे पर अभियान, कूड़ा फैलाने वालों पर सख्ती और चालान

पथ प्रवाह, हरिद्वार

हरिद्वार शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त नंदन कुमार (आईएएस) ने नगर निगम कार्यालय में सभी मुख्य सफाई निरीक्षकों एवं सुपरवाइजरों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक कर चीनी मांझे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, शहर की समग्र स्वच्छता व्यवस्था तथा आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों की गहन समीक्षा की।

बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि चीनी मांझा केवल एक कानून-व्यवस्था या दुर्घटना से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह गंभीर स्वच्छता, प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट का कारण बन चुका है। उन्होंने कहा कि इसकी अनदेखी शहर की छवि, जनसुरक्षा और स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग–तीनों को प्रभावित करती है।

चीनी मांझा: जानलेवा भी, गंदगी का बड़ा कारण भी

नगर आयुक्त नंदन कुमार ने अधिकारियों को बताया कि चीनी मांझा प्लास्टिक और नायलॉन से निर्मित होता है, जो वर्षों तक नष्ट नहीं होता। उपयोग के बाद यह बिजली के खंभों, पेड़ों, छतों, सड़कों और नालियों में लटककर न केवल शहर की सुंदरता को खराब करता है, बल्कि गंभीर स्वच्छता समस्या भी पैदा करता है। नालियों में फंसा मांझा जल निकासी को अवरुद्ध कर जलभराव, दुर्गंध और गंदगी को जन्म देता है। पशु-पक्षी इसके कारण घायल होते हैं और कई बार मृत्यु तक हो जाती है, जिससे यह विषय मानवीय ही नहीं बल्कि जैव विविधता से भी सीधे जुड़ जाता है।

बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

नगर आयुक्त नंदन कुमार ने चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग को लेकर कठोर प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसे प्रतिबंधित प्लास्टिक और गंदगी के खिलाफ चल रहे अभियानों के साथ जोड़कर एक संयुक्त विशेष अभियान के रूप में लागू किया जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि गंदगी फैलाने वालों पर नियमित चालान किए जाएं, प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जाए, सार्वजनिक स्थलों से लटके चीनी मांझे की तत्काल सफाई सुनिश्चित हो, आमजन को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार तेज किया जाए।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 पर विशेष फोकस

बैठक में आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर फील्ड स्तर की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि स्वच्छता, प्लास्टिक नियंत्रण और जनसुरक्षा–तीनों एक-दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं और इन्हें अलग-अलग नहीं, बल्कि एकीकृत रणनीति के तहत लागू किया जाना चाहिए।

बैठक में एसएनए ऋषभ उनियाल, मुख्य सैनिटरी निरीक्षक मनोज कुमार, धीरेन्द्र सेमवाल, अर्जुन सिंह, संजय शर्मा, श्रीकांत, विकास चाचर, विकास चौधरी, सुनील मलिक एवं सुरेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

हरिद्वार कोर्ट ने नीटू हत्याकांड में आरोपी छोटा की जमानत याचिका की खारिज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में हुए सनसनीखेज नीटू हत्याकांड में हरिद्वार न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण वोहरा की अदालत ने आरोपी छोटा की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। शासकीय अधिवक्ता वीरेश चंद कौशिवा ने बताया कि 17 जुलाई 2025 को सिडकुल क्षेत्र में नीटू की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया था। घटना के तीन दिन बाद मृतक के बड़े भाई राकेश सिंह ने सिडकुल थाने में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच और कॉल डिटेल के आधार पर नीटू की हत्या में आरोपी छोटा और अकबर की भूमिका सामने आई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शिकायतकर्ता की पत्नी सोनिया पर नीटू के हिस्से के मकान पर कब्जा करने की नीयत से हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के अनुसार सोनिया ने पांच लाख रुपये की सुपारी देकर देवर नीटू की हत्या करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर पर गंभीर चोटें पाई गई थीं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी छोटा पुत्र शहीद, निवासी ग्राम हजारा ग्रांट, सिडकुल की जमानत याचिका खारिज कर दी।

हरिद्वार में 16 जनवरी को सभी स्कूल-आंगनबाड़ी बंद, ऑरेंज अलर्ट जारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा जारी 7 दिवसीय जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी के तहत हरिद्वार जनपद में 16 जनवरी 2026 को घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने और कुछ स्थानों पर शीतलहर/शीत दिवस की स्थिति की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम चेतावनी के मद्देनज़र विद्यार्थियों और छोटे बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने जनपद के समस्त शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों (नर्सरी से कक्षा 12 तक) तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 16 जनवरी 2026 को पठन-पाठन कार्य पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, विद्यालय प्रबंधन छात्रहित में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य संचालित कर सकते हैं। वहीं बोर्ड परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं एवं प्री-बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलों एवं संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना करने वाले किसी भी विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

भगवान शिव की भक्ति में डूबे यो यो हनी सिंह, नीलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक

पथ प्रवाह, हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार एक ऐसी पुण्यभूमि है, जहां जो भी एक बार आता है, उसका मन बार-बार यहां खिंचा चला आता है। मां गंगा की अविरल धारा, भगवान भोलेनाथ की कृपा और संतों का सान्निध्य–यहां हर किसी को अध्यात्म से जोड़ देता है। यही कारण है कि हरिद्वार आकर चाहे कोई आम श्रद्धालु हो या देश-दुनिया की नामचीन हस्ती, सभी पर भक्ति का अलग ही रंग चढ़ जाता है। बॉलीवुड के मशहूर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह हरिद्वार पहुंचकर अध्यात्म के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। अपने कई इंटरव्यू में वह इस बदलाव का जिक्र भी कर चुके हैं। इसी कड़ी में हनी सिंह एक बार फिर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचते ही हनी सिंह सीधे नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। मंदिर परिसर में हनी सिंह पूरी तरह भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए। शांत मन, सादगी और श्रद्धा के साथ उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी हनी सिंह कई बार हरिद्वार आ चुके हैं। जब-जब वह धर्मनगरी आते हैं, नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। हनी सिंह का यह आध्यात्मिक रुझान उनके प्रशंसकों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का आंदोलन तेज, हरिद्वार से गेट मीटिंग अभियान की शुरुआत

पथ प्रवाह, हरिद्वार

राज्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 15 जनवरी से प्रस्तावित आंदोलन के प्रथम चरण के तहत गेट मीटिंग अभियान की शुरुआत आईटीआई जगजीतपुर, हरिद्वार से की गई। परिषद के सभी घटक संगठनों ने गेट मीटिंग में पूर्ण मनोयोग के साथ भागीदारी करते हुए सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ी प्रमुख मांगों–पुरानी एसीपी, गोल्डन कार्ड की विसंगतियों तथा वेतन विसंगति के प्रकरणों–पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे प्रदेशभर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते प्रांतीय नेतृत्व ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत गेट मीटिंग के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार के सभी विभागों के कर्मचारी इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

परिषद की जिला सचिव अंकुर चौहान ने गेट मीटिंग में सहयोग देने वाले सभी घटक संघों के जिला अध्यक्षों एवं जिला सचिवों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी संगठनों ने एकजुट होकर उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर परिषद की 18

सूत्रीय मांगों के निस्तारण में लगातार हीला-हवाली की जा रही है, जिसके चलते आंदोलन अनिवार्य हो गया था।

गेट मीटिंग में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में अनुज चौहान, गीता शर्मा, मोहित कुमार, भूषण कुमार, प्रदीप प्रजापति, उस्मान अली, दिनेश कुमार, गोपाल सिंह, संगीता बेलवाल, रेशमा चौहान, पूरण कुमार, राधेश्याम, दीपक कुमार, वासिन अली, राजेश कुमार एवं इरशाद अली सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला सचिव अंकुर चौहान ने बताया कि प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा इस प्रकार तय की गई है– प्रथम चरण में 15 से 31 जनवरी 2026 तक विभिन्न कार्यालयों में गेट मीटिंग के माध्यम से जनजागरण किया जाएगा।

द्वितीय चरण में 7 फरवरी 2026 को जनपद स्तर पर धरना देकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।

तृतीय चरण में 21 फरवरी 2026 को राजधानी देहरादून में प्रदेश स्तरीय धरना आयोजित होगा।

चतुर्थ चरण में 22 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक क्षेत्रीय विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे।

पंचम एवं अंतिम चरण में 13 मार्च 2026 को देहरादून में परेड ग्राउंड से सचिवालय तक प्रदेश स्तरीय रैली निकाली जाएगी। परिषद नेताओं ने कहा कि यदि इसके बाद भी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

यातायात में बाधा बन रहे हाईमाक्स विद्युत पोल को एनएचएआई ने हटाया

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

चंडी चौक पर यातायात में बाधा बन रहे हाईमास्क विद्युत पोल को एनएचएआई की टीम ने गुरूवार को हटा दिया। इस पोल के हटने से अब यहां यातायात बाधित नहीं होगा। हटाए गए हाईमास्क लाइट को दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा ताकि यहां चौक पर रोशनी बनी रहे। अतुल शर्मा प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआई ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को बाधित कर रहे पोल, होर्डिंग, यूनिपोल को जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जिला सड़क सुरक्षा समिति हरिद्वार हटाया जा रहा है। अभियान के दौरान सभी प्रकार के मार्गों पर यातायात को अवरुद्ध कर रहे, किसी भी प्रकार के साइन बोर्ड, होर्डिंग, यूनिपोल या अन्य किसी प्रकार के अवरोध को हटाए जा रहे हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा एवं नेहा झा के द्वारा चिन्हित हाई माक्स लाइट पोल, जो कि चंडी चौक चौराहे पर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर हरिद्वार से नजीबाबाद जाने वाले यातायात को प्रभावित कर रहा था। उसे भी हटाने की संस्तुति की गई थी। इस पोल की वजह से दुर्घटना होने की संभावना हर समय बनी रहती थी। इसका संज्ञान लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रुड़की के साइट इंजीनियर नवीन सिंह रावत, यातायात पुलिस, नगर निगम एवं अन्य के सहयोग से उक्त हाई मास्क लाइट के पॉल को चंडी चौक

से हटा दिया गया है। साथ ही संबंधित टीम को निर्देशित कर उस पोल की फाउंडेशन को भी हटाने के साथ-साथ सड़क को स्मूथ करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि चंडी चौक पर अब बाधा रहित यातायात का संचालन निरंतर होता रहेगा एवं दुर्घटनाओं की आशंका भी शून्य होगी। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि चण्डी चौक चौराहे पर बनी रोटरी के चारों तरफ लगे पोस्टर बैनर को पैट्रोलिंग टीम द्वारा हटाया गया।

स्मार्ट तकनीकों से सशक्त होगा स्वास्थ्य तंत्रः आचार्य बालकृष्ण

पथ प्रवाह, हरिद्वार

आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आज सनातन संस्कृति का गौरव वैश्विक स्तर पर स्थापित हो रहा है और आधुनिक स्मार्ट तकनीकों के समन्वय से स्वास्थ्य सेवा एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, प्रकृति-सम्मत और मानव कल्याण की आधारशिला है। वे पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित 'स्वास्थ्य सेवा और प्रबंधन में स्मार्ट तकनीकों के एकीकरण' विषयक त्रिदिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे।

आचार्य बालकृष्ण ने 'सहस्त्र चंद्र दर्शन' की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दीर्घायु, स्वस्थ और ज्ञानपूर्ण जीवन का उत्सव है, जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। उन्होंने कहा कि सनातन के मूल सिद्धांत कृषि और किसान के जीवन से जुड़े हैं, जहां प्राकृतिक खेती, पंचमहाभूतों के सम्मान और प्रकृति से सामंजस्य के माध्यम से संतुलित जीवन की अवधारणा निहित है। भूमंडलीकरण के दौर में 'वसुधैव कुटुंबकम' का सिद्धांत वैश्विक एकता और साझा उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करता है।

उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वियरेबल सेंसर, कनेक्टेड मेडिकल पंप और स्मार्ट अस्पताल उपकरण इंटरनेट व सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य डेटा का संग्रह, साझा और विश्लेषण संभव होता है और चिकित्सा सेवाएं अधिक प्रभावी बनती हैं।

पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से ग्लोबल नॉलेज फाउंडेशन, भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ईस्टर्न शोर के बिजनेस, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग विभाग की सहभागिता रही। संगोष्ठी का आयोजन 15 से 17 जनवरी तक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन एवं विश्वविद्यालय के सहयोग से सभागार में किया जा रहा है।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, धन्वंतरि वंदना और समूहगान से हुआ। कुलपति प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन देते हुए संगोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात सार पुस्तक का लोकार्पण किया गया।

डॉ. देव शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि एआई आधारित चिकित्सा प्रणाली व्यक्तिगत उपचार चयन विश्लेषण को अधिक सटीक बना रही है। उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और एआई-सहायित प्रणालियों के माध्यम से सुरक्षित एवं उन्नत चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता बताई।

आईआईटी मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि एआई आज जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसके साथ नैतिकता का होना अनिवार्य है। उन्होंने टेलीमेडिसिन को स्वास्थ्य सेवाओं की एक उभरती हुई और प्रभावशाली विधा बताया।

भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक सचिन चौधरी ने कहा कि गुणवत्ता, मानक और सुरक्षा सुनिश्चित करना बीआईएस की प्राथमिकता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वसनीयता बढ़ती है। वहीं आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. कमलकिशोर पंत ने डिजिटल स्वास्थ्य, एआई और भारतीय संस्कृति के वैश्विक महत्व पर विचार रखे।

पतंजलि हर्बल रिसर्च की अनुसंधान प्रमुख डॉ. वेदप्रिया आर्या ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एग्रीटेक, मृदा परीक्षण, अनुसंधान एवं एआई आधारित व्यावहारिक कार्यों को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा।

एक नजर

पेट्रोल की कालाबाज़ारी, 600 लीटर अवैध पेट्रोल जब्त

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिले में अवैध पेट्रोल बिक्री के खिलाफ पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य के निर्देश पर गठित विभागीय टीम ने ग्राम भोगपुर में छापेमारी कर डीजल के नाम पर अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया।

छापेमारी के दौरान मौके से दो ड्रमों में भरा लगभग 600 लीटर अवैध पेट्रोल बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से डीजल की आड़ में पेट्रोल बेचकर अवैध मुनाफा कमा रहा था। पूर्ति विभाग द्वारा संबंधित आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं में तहरीर दी जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कालाबाज़ारी और अवैध ईंधन बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

दुष्कर्म मामले में लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार, विवाहिता की शादी तुड़वाने का भी आरोप

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नगर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर विवाहिता के साथ शारीरिक शोषण करने, अश्लील गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने के साथ ही उसके ससुराल पक्ष को लगातार फोन कर उसकी शादी तुड़वाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, 6 दिसंबर 2025 को पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली नगर में कुशल पाल (35) पुत्र अनिल कुमार सैनी, निवासी बैरागी कैंप, थाना कनखल, जनपद हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए तथा मोबाइल फोन के माध्यम से उसे अश्लील गालियां दीं। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी स्त्री लज्जा भंग की और लैंगिक उत्पीड़न किया। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी के साथ उसके पहले से प्रेम संबंध थे। शादी हो जाने के बाद भी आरोपी लगातार उसे और उसके ससुराल पक्ष को फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। आरोपी की इन हरकतों के कारण पीड़िता का वैवाहिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और अंततः उसकी शादी टूट गई। एसएसआई नंद किशोर ग्वाड़ी ने बताया कि मामले में वांछित चल रहे आरोपी कुशल पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि शादी से पहले आरोपी और पीड़िता के बीच संपर्क था, लेकिन शादी के बाद आरोपी द्वारा लगातार परेशान किए जाने के कारण पीड़िता को गंभीर मानसिक और सामाजिक परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक निशा सिंह, कांस्टेबल सुमित और कांस्टेबल हरीश रतूड़ी शामिल रहे। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

सुधांशु वत्स अखिल भारतीय सनातन परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त

पथ प्रवाह, हरिद्वार

अखिल भारतीय सनातन परिषद के विस्तार और संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। परिषद के संस्थापक अध्यक्ष श्री महंत डॉ. रवींद्र पुरी जी महाराज एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार बत्रा ने संयुक्त रूप से सुधांशु वत्स को परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया है। इस अवसर पर श्री महंत डॉ. रवींद्र पुरी महाराज ने सुधांशु वत्स को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और सांगठनिक अनुभव से सनातन परिषद को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि सुधांशु वत्स सनातन धर्म के मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने और परिषद की गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार बत्रा ने कहा कि सुधांशु वत्स की नियुक्ति से संगठन के प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों में गति आएगी। अपनी नियुक्ति पर सुधांशु वत्स ने नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा के साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित रहेंगे।

मंगलौर पुलिस की शराब तस्करी पर सर्जिकल स्ट्राइक, 10 टायरा ट्रक से 300 पेटी बरामद

पथ प्रवाह, हरिद्वार

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देशन में मकर संक्रांति पर्व के दृष्टिगत जनपदभर में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत हरिद्वार जनपद की मंगलौर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय शराब तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 10 टायरा ट्रक सहित 300 पेटी हरियाणा ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में ट्रक चालक को मौके से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को चौकी लण्ढौरा क्षेत्र में विशेष इनपुट के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक 10 टायरा ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने ट्रक में केमिकल ले जाने की बात कही, लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों और बार-बार की आनाकानी के चलते पुलिस टीम ने कंटेनर की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक के अंदर से 300 पेटी सुपर जुबली स्पेशल व्हिस्की (हरियाणा ब्रांड) बरामद हुई।

पूछताछ में आरोपी चालक ने खुलासा किया कि वह यह शराब चंडीगढ़ से लोड कर हरिद्वार, गोरखपुर और कुशीनगर होते हुए बिहार सप्लाई करने जा रहा था। हरिद्वार में

चल रही सख्त चेकिंग और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक के चलते उसने रूट बदलने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने समय रहते उसे दबोच लिया। शराब की तस्करी के लिए केमिकल के बिलों की आड़ लेकर मुनाफा कमाने की साजिश रची गई थी। बरामद शराब के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ कोतवाली मंगलौर में धारा 61(2), 318(4) बीएनएस तथा आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ट्रक, शराब की खेप और एक मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पकड़े गए आरोपी का विवरणः

रविरंजन कुमार राय पुत्र लखिन्द्र राय, निवासी सुन्दरपुर बिरियापुर, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार)।

बरामद मालः सुपर जुबली स्पेशल व्हिस्की (हरियाणा ब्रांड) - 300 पेटी, 10 टायरा ट्रक - 01, मोबाइल फोन - 01

पुलिस टीम (कोतवाली मंगलौर)

प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रफत अली, उपनिरीक्षक राकेश डिमरी, उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह, कांस्टेबल केडी राणा, कांस्टेबल मोहम्मद आमिर।

सीआईयू टीम रुड़की

निरीक्षक प्रदीप विष्ट, अपर उपनिरीक्षक अश्वनी यादव, हेड कांस्टेबल चमन, हेड कांस्टेबल मनमोहन भण्डारी, कांस्टेबल राहुल नेगी, कांस्टेबल महिपाल सिंह, कांस्टेबल अजय काला।

संपादकीय

उत्तराखंड में जंगली जानवर और आग: बढ़ती मुसीबत का सबब

उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और जैव विविधता के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यही जंगल और उनमें रहने वाले जंगली जानवर राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। जंगली जानवरों का आबादी वाले इलाकों में बढ़ता दखल और जंगलों में लगने वाली आग, दोनों ही समस्याएं आज उत्तराखंड के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन चुकी हैं।

प्रदेश के पर्वतीय और तराई क्षेत्रों में बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में खेतों की फसलें नष्ट हो रही हैं, मवेशियों पर हमले हो रहे हैं और कई बार मानव जीवन तक खतरे में पड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण जंगलों का सिकुड़ना, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, सड़क-रेल परियोजनाएं और प्राकृतिक जलस्रोतों का सूखना है। जब जंगलों में भोजन और पानी की कमी होती है, तो जंगली जानवरों का रुख गांवों और कस्बों की ओर होना स्वाभाविक है।

दूसरी ओर, हर साल गर्मियों के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग समस्या को और भयावह बना देती है। जंगल की आग से न केवल लाखों पेड़-पौधे और वन्यजीवों का नुकसान होता है, बल्कि इससे पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता है। धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरता घटती है और जलस्रोत प्रभावित होते हैं। आग के बाद जानवर अपने प्राकृतिक आवास से बेघर हो जाते हैं, जिससे उनका मानव बस्तियों की ओर आना और बढ़ जाता है।

सरकार और वन विभाग द्वारा समय-समय पर कई प्रयास किए गए हैं, जैसे सोलर फेंसिंग, ट्रेंच खोदना, अलर्ट सिस्टम और मुआवजा योजनाएं। लेकिन जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव सीमित ही नजर आता है। कई बार मुआवजा समय पर नहीं मिल पाता, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता है। जंगलों की आग रोकने के लिए भी निगरानी तंत्र और स्थानीय सहभागिता को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाए। जंगलों का संरक्षण, जलस्रोतों का पुनर्जीवन, वन्यजीव कॉरिडोर का विकास और स्थानीय लोगों को वन प्रबंधन में भागीदार बनाना बेहद जरूरी है। साथ ही, जनजागरूकता और त्वरित राहत तंत्र को प्रभावी बनाकर ही उत्तराखंड को इस दोहरी मुसीबत–जंगली जानवर और जंगल की आग–से सुरक्षित किया जा सकता है।

ट्रंप के दौर में अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में?

सनत कुमार जैन

अमेरिका लंबे समय से स्वयं को दुनिया के सबसे मजबूत आर्थिक एवं लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से उनकी छवि पर गंभीर सवाल सारी दुनिया में खड़े हो गए हैं। ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका की वरन अंतरराष्ट्रीय संस्थागत मर्यादाओं को चुनौती देने का काम किया है। अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया, न्यायपालिका, मीडिया और लोकतांत्रिक परंपराओं, वैश्विक व्यापार संधि और वैश्विक संस्थाओं पर सीधा हमला किया है । 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद अब वह एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुआ हमला इस बात का प्रमाण है। ट्रंप की सत्ता की लालसा उन्हें किस हद तक ले जाकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। उक्त घटना केवल अमेरिका की आंतरिक समस्या नहीं थी। वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी यह एक चेतावनी थी। ट्रंप की राजनीति ने अमेरिकी समाज को गहरे अंधेरे में धकेल दिया है। नस्ल, धर्म, प्रवासियों और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर उग्र बयानबाजी ने ट्रंप और अमेरिका की असहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को लेकर अमेरिका को सारी दुनिया में कमजोर करने का काम किया है। बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर अमेरिका की विश्वसनीयता लगभग खत्म हो गई है। जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश ही लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने से इंकार करे, तो उसका असर स्वाभाविक रूप से दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता है।

अब इसका प्रभाव यूरोप में भी नजर आने लगा है। कई यूरोपीय देशों में दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होना शुरू हो गई हैं। जिसके कारण लोकतंत्र और मानव अधिकार को लेकर भरोसा कमजोर हो रहा है। युवा पीढ़ी भविष्य को लेकर गहरी निराशा में है। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता ने युवाओं को असुरक्षा की भावना से भर दिया है। कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। इस कारण जीवन-यापन की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। रोजगार के अवसर भी बड़ी तेजी के साथ कम होते जा रहे हैं। यूरोप के युवा सवाल पूछ रहे हैं, क्या लोकतांत्रिक सरकारें उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगी? आज विश्व के 60 से ज्यादा देशों में अपनी ही सरकार के खिलाफ लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारें महंगाई रोकने, स्थायी रोजगार देने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल साबित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में कट्टरपंथी विचार धाराओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। यही स्थिति अमेरिका में भी देखी जा रही है। आर्थिक असुरक्षा और असंतोष को ट्रंप राजनीतिक ताकत से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में आवश्यकता है, अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करें। आम जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं। आम लोगों की तथा युवाओं की आर्थिक चिंताओं को प्राथमिकता देकर उनका निराकरण करें।

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं है। नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की उम्मीद की व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यदि यह भरोसा टूटता है, तो खतरे में सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। 1995 में आर्थिक व्यापार संधि के बाद वैश्विक स्तर पर दुनिया के सारे देश एक दूसरे के बहुत करीब आए थे। पूरी सोच बदल गई थी। पिछले दो दशक में दुनिया के सभी देशों में कर्ज को लेकर आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने की जो मुहिम चल रही थी वह अब कर्ज के बोझ से बुरी तरह से दब चुकी है। सारी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा बड़ी तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की उपेक्षा करते हुए मनमानी कर रहे हैं, सारी दुनिया के देशों को टैरिफ के भय तथा अमेरिका की ताकत के आगे झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका खामीयाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है।

सावरमती से आसमान तक पतंगों की बोली में भारत-जर्मनी की दोस्ती की नई ऊँचाई

कांतिलाल मांडोत

साबरमती रिवरफ्रंट से जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक साथ पतंग उड़ाई, तो वह दृश्य केवल उत्तरायण के उल्लास का प्रतीक नहीं था, बल्कि भारत-जर्मनी संबंधों की उस उड़ान का संकेत भी था, जो संस्कृति से लेकर रणनीति और व्यापार से लेकर तकनीक तक नए आयाम छू रही है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आईकेएफ-2026

का शुभारंभ एक ऐसे मंच पर हुआ, जहाँ रंगीन पतंगों के साथ-साथ कूटनीति, आर्थिक सहयोग और रक्षा साझेदारी के संदेश भी हवा में घुले हुए थे। अहमदाबाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पोल-हवेलियों की स्थापत्य झलक, पतंग संग्रहालय, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियाँ इन सबने मिलकर यह बता दिया कि भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति के साथ वैश्विक मित्रताओं को कैसे सशक्त करता है।

उत्तरायण गुजरात की आत्मा से जुड़ा पर्व है। यह केवल पतंगबाजी नहीं, बल्कि सामूहिक उत्सव, लोककला, संगीत और परंपरा का संगम है। जब इसी मंच पर जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, तो यह संदेश स्पष्ट था कि भारत अपने मित्र देशों को केवल औपचारिक बैठकों में नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धड़कन में भी आमंत्रित करता है। पोल और हवेली की प्रतिकृतियाँ, कारीगरों द्वारा पतंग निर्माण का जीवंत प्रदर्शन, गरबा रास, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मलखंब जैसी कलाओं की प्रस्तुतियाँ तथा भारतीय और जर्मन धुनों का समन्वय यह सब भारत की सॉफ्ट पावर का प्रभावशाली प्रदर्शन था। ऐसी सांस्कृतिक कूटनीति रिश्तों को केवल समझौतों तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उनमें भावनात्मक मजबूती भी जोड़ती है। इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बीच भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी सामने आया। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को नई ऊँचाई देने वाली प्रोजेक्ट-75 की पनडुब्बी परियोजना इस साझेदारी का प्रतीक बनकर उभरी है। जर्मनी की प्रसिद्ध रक्षा कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स और भारत के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के बीच पहले से हुए समझौते के तहत छह अत्याधुनिक स्टील्थ पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाना प्रस्तावित है। लगभग 8 बिलियन डॉलर, यानी करीब 72 हजार करोड़ रुपये की यह डील भारतीय नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजनाओं में गिनी जा रही है। इन पनडुब्बियों की खासियत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक है, जो उन्हें लंबे समय तक बिना सतह पर आए समुद्र के भीतर ऑपरेशन करने में सक्षम बनाएगी। कम शोर, अधिक स्टील्थ और लंबी अवधि तक छिपे रहने की क्षमता यही वह गुण हैं, जिनकी भारतीय नौसेना को लंबे समय से तलाश थी।

इस डील का महत्व केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। इसका सीधा लाभ 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों को मिलता है। निर्माण भारत में होने से देश के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी, कुशल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण होगा। जर्मनी के लिए यह डील भारत जैसे बड़े और भरोसेमंद साझेदार के साथ दीर्घकालिक सहयोग का अवसर है, जबकि भारत के लिए यह समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को मजबूत करने का साधन बनती है। बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और समुद्री चुनौतियों के दौर में यह साझेदारी भारत की प्रतिरोधक क्षमता को नई धार देती है। भारत और जर्मनी के रिश्ते केवल रक्षा तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग भी निरंतर विस्तार पा रहा है। आज भारत में दो हजार से अधिक जर्मन कंपनियाँ सक्रिय हैं, जो ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, रसायन, ऊर्जा, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। यह संख्या जर्मनी के भारत पर भरोसे और भारत के बढ़ते बाजार सामर्थ्य का प्रमाण है। द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच वार्षिक व्यापार लगभग 26 से 30 बिलियन डॉलर के बीच आंका जाता है, और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं।

जर्मनी से भारत मुख्य रूप से मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जे, रसायन, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मेडिकल टेक्नोलॉजी और उन्नत इंजीनियरिंग उत्पाद आयात करता है। ये वे क्षेत्र हैं, जहाँ जर्मनी की तकनीकी दक्षता विश्वभर में प्रसिद्ध है। दूसरी ओर भारत जर्मनी को वस्त्र, परिधान, चमड़ा उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, आईटी सेवाएँ, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, कृषि-आधारित उत्पाद और इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात करता है। सेवा क्षेत्र में आईटी और डिजिटल समाधान भारत की मजबूत उपस्थिति को दर्शाते हैं, जबकि फार्मा और रसायन क्षेत्र भारत की विनिर्माण क्षमता का उदाहरण हैं।

इस व्यापारिक रिश्ते का लाभ दोनों पक्षों को मिलता है। जर्मनी को भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार तक पहुँच मिलती है, जहाँ युवा आबादी, बुनियादी ढांचे का विस्तार और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं। भारत को जर्मनी से उन्नत तकनीक, गुणवत्ता मानक और नवाचार का लाभ मिलता है, जो घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि दोनों देश केवल पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि स्टार्टअप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं।

कच्छ-सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में निवेश और व्यापारिक सम्मेलनों के जरिए इस सहयोग को जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश दिखाई देती है। बी-टू-बी और बी-टू-जी बैठकों में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, वह बताता है कि स्थानीय उद्यमी, कारीगर, स्टार्टअप्स और तकनीकी विद्यार्थी वैश्विक अवसरों से जुड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे आयोजनों में उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन, पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की तकनीकों पर संवाद न केवल निवेश को आकर्षित करता है, बल्कि ज्ञान और नवाचार के आदान-प्रदान को भी गति देता है।

शब्द, संवेदना और संस्कृति का संगम: दिल्ली पुस्तक मेला-2026

सुनील कुमार महला

स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कही है कि-पुस्तकें वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती हैं।वास्तव में सच तो यह है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे सच्ची मित्र होती हैं, जो बिना कुछ कहे हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। अच्छी किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं और अज्ञान के अंधकार को दूर कर सोचने-समझने की शक्ति विकसित करती हैं। वे अनुभवों, विचारों और संस्कारों से हमें समृद्ध बनाती हैं तथा जीवन भर हमारा साथ निभाती हैं। सच ही कहा गया है कि पढ़ने की आदत मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है और उसे बेहतर इंसान बनाती है। वहीं पर पुस्तक मेला ज्ञान, विचारों और संस्कृति के आदान-प्रदान का जीवंत मंच होता है, जहां पाठकों को नई-पुरानी पुस्तकों, लेखकों और प्रकाशकों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलता है। यह पठन-पाठन की रुचि को बढ़ावा देकर समाज में बौद्धिक चेतना को मजबूत करता है। साथ ही, पुस्तक मेला साहित्य, शिक्षा और रचनात्मकता को जन-जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाता है। इस क्रम में,हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में आयोजित दिल्ली विश्व पुस्तक मेला-2026 (53वां संस्करण) दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। यह भव्य आयोजन 10 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 तक, कुल 9 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस विशाल साहित्यिक उत्सव का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट (एनबीटी) द्वारा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के सहयोग से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का 53वां संस्करण भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट की ओर से ही आयोजित किया गया है।पाठकों को बताना चाहूंगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 जनवरी 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने पुस्तक 'द सागा ऑफ कुडोपाली: 1857 की अनकही कहानी' का विमोचन किया, जिसे हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं और स्पेनिश भाषा में प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक ओडिशा के संबलपुर क्षेत्र में वीर सुरेंद्र साई के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक विद्रोह और शहीदों के बलिदान को सम्मानित करती है। इस वर्ष का पुस्तक मेला कई मायनों में विशेष है, क्योंकि पहली बार प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। मेले में 30 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक और लगभग 3000 स्टॉल शामिल हैं, जहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी सहित अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं की पुस्तकों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। इस बार मेले की मुख्य थीम -'भारतीय सैन्य इतिहास: वीरता और बुद्धिमत्ता ञ्च75' (इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री:वेलोर एंड विज्डम) रखी गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, इतिहास और योगदान को साहित्य और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।थीम मंडप लगभग 1000 वर्ग मीटर में फैला एक अत्याधुनिक इमर्सिव (त्रि-आयामी) अनुभव प्रदान करता है, जहाँ भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। यहाँ अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस के आदमकद मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, जो मेले के प्रमुख आकर्षण हैं। साथ ही, देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं को विशेष श्रद्धांजलि भी दी गई है।इस पुस्तक मेले में 600 से अधिक साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेखक संवाद, कवि सम्मेलन तथा बच्चों के लिए विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जिससे यह मेला लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों के लिए एक भव्य साहित्यिक उत्सव बन गया है। आज के डिजिटल, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब पुस्तकों के प्रति रुचि कम होती जा रही है, ऐसे समय में यह मेला विशेष रूप से युवाओं (जेन-जेड) और बच्चों में पठन संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।मेले में कला और संस्कृति, इतिहास, सिनेमा, व्यक्तित्व और जीवनियाँ, भूमि और लोग, गांधीवादी साहित्य तथा बाल साहित्य जैसे विविध विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। प्रीमियम पुस्तकों की श्रेणी में 'राष्ट्रपति भवन श्रृंखला', राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चयनित भाषण, महात्मा गांधी की रचनाएँ तथा पंडित मदन मोहन मालवीय की रचनाएँ विशेष रूप से शामिल हैं। पुस्तकों के समृद्ध संग्रह के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग भी मेले में अपनी प्रसिद्ध पत्रिकाएँ योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती प्रदर्शित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आगंतुक यहाँ से रोजगार समाचार की वार्षिक सदस्यता भी खरीद सकते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित आयोजन है, जिसमें देश-विदेश के नामचीन प्रकाशक भाग लेते हैं। यहाँ पुस्तक विमोचन, लेखक से मिलने के कार्यक्रम, युवाओं और बच्चों के लिए विशेष गतिविधियाँ तथा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाती हैं, जिनका आगंतुक भरपूर आनंद लेते हैं। कालजयी कृतियों से लेकर समकालीन लेखन, बाल साहित्य, अनुवाद और विचारोत्तेजक चर्चाओं तक, यह मेला प्रकाशकों, लेखकों और पाठकों को एक जीवंत मंच पर एकत्र करता है।वास्तव में, पुस्तकें ज्ञान की वाहक होती हैं, जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं, सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोती हैं और समाज को दिशा देती हैं। इसी कारण किसी भी पुस्तक मेले का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत व्यापक होता है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में आयोजित यह पुस्तक मेला विश्वभर के प्रकाशकों के लिए एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है। जानकारी के अनुसार, इस बार मेले में करीब 20 लाख से अधिक पाठकों के आने की उम्मीद है।इस मेले का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करना है, ताकि निःशुल्क प्रवेश के माध्यम से आर्थिक स्थिति किसी के पठन और शिक्षा के मार्ग में बाधा न बने। साथ ही, डिजिटल और पारंपरिक पठन के संगम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय के माध्यम से डिजिटल रीडिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेले में लगाए गए डिजिटल कियोस्क से पाठक 6000 से अधिक निःशुल्क ई-बुक्स क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मंत्रिमंडल के अहम फैसले: किसानों, कर्मचारियों, न्याय व्यवस्था, पर्यटन और पर्यावरण पर निर्णय

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन निर्णयों का सीधा लाभ किसानों, कर्मचारियों, युवाओं, न्यायिक व्यवस्था, पर्यटन, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े क्षेत्रों को मिलेगा।

चीनी मिलों को राहत, किसानों के हित सुरक्षित

मंत्रिमंडल ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने हेतु 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति देने का अनुमोदन किया। इसके तहत डोईवाला, किच्छा, नादेही एवं बाजपुर चीनी मिलें शामिल हैं।

साथ ही गन्ना किसानों के हित में पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया। अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल एवं सामान्य प्रजाति के लिए 395 रुपये प्रति कुंतल (मिल गेट) तय किया गया। गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) 5.50 रुपये प्रति कुंतल यथावत रहेगा।

निर्वाचन विभाग, संस्कृत और विज्ञान को मजबूती

मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग के निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की। संस्कृत के प्रचार-प्रसार को नई पहचान देते हुए 'उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी' का नाम बदलकर 'उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम्' करने

का निर्णय लिया गया। यू-कॉस्ट के अंतर्गत अल्मोड़ा एवं चम्पावत विज्ञान केंद्रों के लिए कुल 12 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

वित्तीय प्रतिवेदन और लेखा परीक्षण को हरी झंडी

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लेखों की सम्परीक्षा प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

बागवानी किसानों को अतिरिक्त सहायता

ओलावृष्टि से फसलों को बचाने हेतु एन्टीहेल नेट योजना में भारत सरकार की 50 प्रतिशत सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश देने का निर्णय लिया गया। इससे सेब, आड़ू, प्लम, नाशपाती सहित अन्य फलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

दून विश्वविद्यालय में हिन्दू अध्ययन केन्द्र को बल

दून विश्वविद्यालय, देहरादून में स्थापित हिन्दू अध्ययन केन्द्र के लिए 6 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई, जिसमें 4 शैक्षणिक एवं 2 शिक्षणेत्तर पद शामिल हैं।

उपनल कर्मियों को समान वेतन का लाभ

मंत्रिमंडल ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को चरणबद्ध रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों को यह लाभ प्रदान किया जाएगा।

न्याय व्यवस्था को मजबूती

NDPS, POCSO, NI Act, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं PMLA से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालयों के गठन तथा कुल 144 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

विधानसभा सत्र, खनन और खेलों पर फैसले

उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के प्रथम आय-व्ययक सत्र को आहूत करने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। खनन विभाग से संबंधित अधिसूचना में 'नन्धौर' के स्थान पर 'नन्धौर एवं अन्य नदियां' शब्द जोड़ने का निर्णय लिया गया। खेल महाकुम्भ के अंतर्गत विधायक, सांसद एवं मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के साथ क्रमशः 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया।

ब्रिडकुल को नई जिम्मेदारियां

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम (ब्रिडकुल) के कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए उसे रोपवे, ऑटोमेटेड पार्किंग तथा टनल पार्किंग निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था सूची में शामिल किया गया।

न्यायिक प्रक्रिया और यूसीसी में सुधार

'उत्तराखण्ड दस्तावेजों की सूची प्रारूप नियमावली, 2025' को मंजूरी देकर न्यायालयी दस्तावेजों को मानकीकृत किया गया। साथ ही समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड में व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु संशोधन अध्यादेश लाने पर सहमति दी गई।

पर्यटन और होम स्टे नियमावली 2026 लागू

नई पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड-एण्ड-ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत होम स्टे योजना का लाभ अब केवल राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

केदारनाथ में पर्यावरण संरक्षण की पहल

श्री केदारनाथ धाम में खच्चरों के गोबर एवं चीड़ की पत्तियों से पर्यावरण अनुकूल बायोमास ईंधन पेलेट बनाने हेतु एक वर्ष की पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे स्वच्छता के साथ-साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

इन निर्णयों के माध्यम से मंत्रिमंडल ने विकास, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

जन-जन तक सरकार, 3.47 लाख शिविर, 1.89 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल, संवेदनशील और जनोन्मुखी नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसमस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है। 15 जनवरी 2026 तक की दैनिक प्रगति रिपोर्ट इस बात की सशक्त पुष्टि करती है कि सरकार सीधे जनता तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है।

उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, प्रदेश के सभी जनपदों में अब तक पिछले दिवस तक 328 शिविरों का आयोजन किया जा चुका था, जबकि आज 19 नए शिविर आयोजित किए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर 347 शिविरों के माध्यम से जनता को सीधे प्रशासनिक सेवाओं से जोड़ा गया है। इन शिविरों में पिछले दिवस तक 2,54,137 नागरिकों ने प्रतिभाग किया, जबकि आज 23,517 नागरिकों की सहभागिता रही, जिससे कुल प्रतिभागियों की संख्या 2,77,654 तक पहुँच गई है। यह आँकड़ा जनविश्वास और सरकार की पहुँच को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जनसमस्याओं के समाधान की दृष्टि से भी यह कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। अब तक 20,814 शिकायतें प्राप्त हो चुकी थीं, जिनमें आज 1,479 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल 22,293 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 18,168 शिकायतों का पूर्व में निस्तारण किया जा चुका था तथा आज 807 शिकायतों का समाधान किया गया, जिससे कुल 18,973 शिकायतों का सफल निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। यह उपलब्धि सरकार की त्वरित कार्यप्रणाली और जवाबदेही को रेखांकित करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को प्रमाण पत्र एवं लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया भी निरंतर गति से आगे बढ़ी है। 36,753 प्रकरणों में पूर्व में लाभ प्रदान किए गए थे, जबकि आज 1,502 नए मामलों में प्रमाण पत्र अथवा लाभ वितरित किए गए। इस प्रकार कुल 38,255 नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, जो सेवा वितरण की प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 1,38,011 नागरिक पूर्व में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो चुके थे, जबकि आज 13,554 नए लाभार्थी जोड़े गए। इस प्रकार कुल 1,51,565 नागरिकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा चुका है, जो सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का सेतु है।

प्रधानमंत्री शिलान्यासित परियोजनाओं की प्रगति पर मुख्य सचिव की सख्त समीक्षा

91 परियोजनाओं पर नजर, मार्च 2026 तक अधिकांश पूर्ण होने की उम्मीद

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर शिलान्यास की गई परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन जिनका अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ है, उनका शीघ्र लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ मिल सके। गतिमान परियोजनाओं के संबंध में उन्होंने विभागों को प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में एक से अधिक विभाग जुड़े हैं, वे आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का समाधान कर कार्य को गति

दें। साथ ही नियोजन विभाग को प्रधानमंत्री के शिलान्यास से संबंधित सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने एमडी यूजेवीएनएल को लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए केंद्रीय जल आयोग को शीघ्र डिजाइन और शेड्यूल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न विभागों की कुल 22,015.76 करोड़ रुपये लागत की 91 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इनमें से 18 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिनमें 6 का लोकार्पण किया जा चुका है, जबकि 12 का लोकार्पण अभी शेष है। शेष 73 परियोजनाओं पर कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जिनमें से अधिकांश के मार्च 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव नीतेश कुमार झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. एस. एन. पाण्डेय, युगल किशोर पंत, अपर सचिव विनीत कुमार एवं नवनीत पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर उपनल कर्मचारियों ने समान कार्य-समान वेतन के संबंध में आज राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को पूरा करने के साथ-साथ उनके सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों में उत्साह एवं विश्वास का वातावरण बना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मियों के हितों की रक्षा, उनके सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके योगदान को सरकार पूरी गंभीरता से मान्यता देती है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों

के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। इस अवसर पर उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे सरकार की नीतियों एवं निर्णयों के अनुरूप पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

एक नजर

कक्षा 11 के छात्र ने घर में फांसी लगाकर किया सुसाइड

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में 11वीं कक्षा के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभिनव चौहान (17 वर्ष) पुत्र समीर उर्फ कुलदीप चौहान के रूप में हुई है। अभिनव 11वीं कक्षा का छात्र था। वह परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता फरीदाबाद में एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। परिजनों के मुताबिक बीती रात करीब दो बजे अभिनव खाना खाकर अपने कमरे में गया था। रात तीन बजे तक किसी से फोन पर बात करता रहा। इसके बाद सुबह जब मां कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि अभिनव फांसी के फंदे से लटका हुआ था। यह देख मां बदहवास हो गईं और परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेने के बाद शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस के मुताबिक मौके से फिलहाल कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहन है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

मंत्री रेखा आर्या ने सड़क का भूमिपूजन किया

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड ताकुला के अंतर्गत मनान से चंद्रपुर तक मोटर मार्ग के 2 किलोमीटर सड़क के नवनिर्माण कार्य का आज भूमिपूजन किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्वयं जेसीबी चलाकर शिलान्यास किया। इस कार्य की स्वीकृत लागत 53.04 लाख रुपये है। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोगों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है। सोमेश्वर क्षेत्र में इसका जीवंत प्रमाण देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि विकास कार्यों की कोई भी मांग हो, तो सबसे पहले उनसे संपर्क करें। ऐसी मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस विकास कार्यों को अटकाने और भटकाने की राजनीति करती है जबकि भाजपा का एक ही लक्ष्य है तीव्र विकास। प्रदेश की भाजपा सरकार इसी लक्ष्य को लेकर चल रही है।

व्यापारी कल्याण बोर्ड गठन की मांग को लेकर हरिद्वार में जोरदार स्वागत, चेयरमैन ने दिया सकारात्मक आश्वासन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के चेयरमैन सुनील जे. सिंघी और दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन के हरिद्वार आगमन पर व्यापारिक संगठनों ने भव्य स्वागत किया। राज्य व्यापार मंडल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र चौटाला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

स्वागत अवसर पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित अरोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष तेज प्रकाश साहू, विजय प्रजापति, प्रदेश कोषाध्यक्ष विशाल गोस्वामी, महानगर अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, महामंत्री अनन्त पांडे, उपाध्यक्ष सोनल गर्ग, ब्रह्मपुरी व्यापार मंडल अध्यक्ष मास्टर मुन्ना, प्रचार सचिव गोकुल सिंह रावत सहित मनीष, जसवंत बिष्ट, नितिन शर्मा समेत अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन, व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा, समस्याओं के समाधान और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर संगठन पदाधिकारियों ने चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। चेयरमैन ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि व्यापारी हितों से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में व्यापारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए व्यापारी एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया और 'व्यापारी एकता जिंदाबाद' के नारों के साथ आयोजन का समापन किया।

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने पीएडीयू को लेकर ठाकरे बंधुओं के आरोपों को खारिज किया

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को 'प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट' (पीएडीयू) के उपयोग को लेकर ठाकरे बंधुओं की केआरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह उपकरण केवल तकनीकी कठिनाइयां आने पर ही इस्तेमाल किया जाएगा और वह भी सिर्फ बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में। आयोग ने कहा कि मुम्बई के बाहर किसी भी नगर निगम में मतगणना के लिए पीएडीयू का उपयोग नहीं किया जाएगा। मुम्बई के भीतर भी इसका उपयोग केवल उन असाधारण स्थितियों तक सीमित रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर दर्ज वोटों की गिनती के दौरान तकनीकी समस्याएं आती हैं।

दिखने लगा स्वच्छता अभियान का असर, चमकने लगे गांव और शहर

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ, स्वच्छ एव सुंदर बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपद में एक माह 28 दिन से निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की निगरानी स्वयं जिलाधिकारी कर रहे हैं।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद को साफ स्वच्छ बनाने के लिए नव वर्ष के अवसर पर महा सफाई अभियान शुरू किया। जिसमें सभी जनपदवासियों ओर धार्मिक संस्थाओं, व्यापार मंडलों, जनप्रतिनिधियों, गैर स्वयंसेवी संगठनों पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई। अभियान के असर से गांव की गलियां और शहर में स्वच्छता नजर आने लगी है। बीएचईएल नगर प्रशासक संजय पवार ने अवगत कराया कि नगर प्रशासन विभाग, बीएचईएल द्वारा बीएचईएल स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं बीएचईएल के मुख्य प्रशासनिक भवन और एसबीआई बैंक के आसपास के क्षेत्र में सफाई कार्य किया गया है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कार्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बहादराबाद बाईपास जंक्शन नजदीक मोहनपूरी वाला के सामने सफाई कार्य किया गया। खण्ड विकास अधिकारी खानपुर ने अवगत कराया कि खानपुर से गोरधनपुर मार्ग पर तथा

गोरधनपुर से सिंकदरपुर कॉम्पैक्टर तक मुख्य मार्ग क्षेत्रांतर्गत साफ़ सफाई का कार्य किया गया। खण्ड विकास अधिकारी रूड़की ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत नन्हेडा, अनंतपुर क्षेत्रांतर्गत साफ़ सफाई का कार्य किया गया। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल द्वारा सफाई अभियान में सहयोग किया जा रहा है, जिसमें युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल ने जौरासी जनतदस्तपुरा, अन्नेकी हेतमपुर, ग्राम डलूवाला के साथ ही रोशनाबाद स्थित कार्यालय परिसर में भी सफाई अभियान चलाया गया। बहादराबाद में युवक मंगल दल डेरा भी सफाई अभियान चलाया गया।

पौड़ी के बाड़ा गांव में गुलदार का कहर: नेपाली मजदूर को बनाया शिकार, ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

पथ प्रवाह, पौड़ी

जिला मुख्यालय से सटे सत्यखाल के समीप बाड़ा गांव में गुरुवार सुबह गुलदार के हमले में नेपाली मूल के एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुलदार को मारने की मांग उठाई।

ग्राम प्रधान नवदीप सिंह बिष्ट ने बताया कि मृतक की पहचान लक्ष्मण साही (करीब 50 वर्ष), निवासी बड़ागांव, सल्यन (नेपाल) के रूप में हुई है। वह गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे गांव के धारे में स्नान करने गया था। बताया गया कि मृतक ने एक दिन पहले प्रधान को बताया था कि उनके प्रांत में गुरुवार को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है, जिसके लिए सुबह स्नान कर पूजा-पाठ किया जाता है। स्नान कर लौटते समय गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्राम प्रधान के भाई सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने दी। उन्होंने बताया कि वह रोज की तरह गांव के शिवालय में पूजा के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में खून दिखाई दिया। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खोजबीन की गई। मुख्य रास्ते से करीब 30 मीटर नीचे झाड़ियों के बीच लक्ष्मण साही का अधखाया शव बरामद हुआ।

सूचना पर पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीण सड़क पर धरने पर बैठ गए और गुलदार को मारने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ महातिम यादव ने बताया कि घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए उसे मारने के आदेश जारी किए गए हैं। क्षेत्र में सोलर सीसीटीवी, कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं और विभागीय शूटरों की टीम तैनात कर दी गई है। वहीं, कोतवाली पुलिस के एसआई प्रवीन रावत ने बताया कि शव का पंचनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है।

कोटद्वार के संरक्षण गृहों में व्यवस्थाओं की परख, जिला निरीक्षण समिति का त्रैमासिक निरीक्षण

बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास पर फोकस : कोटद्वार स्थित संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण

पथ प्रवाह, पौड़ी

जिला निरीक्षण समिति द्वारा महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र, राजकीय सुरक्षा स्थान तथा राजकीय संप्रेषण गृह (किशोरी), कोटद्वार का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य संस्थानों में निवासरत बालिकाओं के लिए उपलब्ध आवास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, मानसिक परामर्श एवं पुनर्वास से संबंधित व्यवस्थाओं का समग्र मूल्यांकन करना था।

परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा संस्थानों की भौतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं, अभिलेखों, दैनिक गतिविधियों तथा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का अवलोकन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला निरीक्षण समिति द्वारा समय-समय पर संस्थानों का निरीक्षण कर बालिकाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। समिति द्वारा संस्थानों में उपलब्ध भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, काउंसलिंग एवं पुनर्वास प्रक्रियाओं को संतोषजनक एवं सुव्यवस्थित पाया गया। निरीक्षण के अवसर पर संस्थानों में निवासरत बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया, जिसमें उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की जांच करते हुए आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि जिला निरीक्षण समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला परिवीक्षा कार्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त संस्थानों में बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता को निरंतर सुदृढ़ किया जाए तथा नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, सीएचओ दीपांजलि, चिकित्सक डॉ. आशीष गुसाईं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आदित्य बड़थ्वाल, मेडिकल इंचार्ज डॉ. चारु रावत, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति राकेश चंद्र, सामाजिक कार्यकर्ता विमल ध्यानी सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सरकार के बहुउद्देशीय शिविर में 1354 लोगों को योजनाओं से किया गया लाभान्वित

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास खंड बहादराबाद के न्याय पंचायत शाहपुर शीतला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से 1109 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया। विभिन्न विभागों के माध्यम से 21 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। शिविर में 3485 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

आयोजित शिविर ने क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 150 समस्याएं दर्ज कराई गई, जिसमें 58 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया,शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री डॉ जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुशल नेतृत्व में जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर हर विधान सभा की ग्राम पंचायत में आयोजित किए जा रहे है,जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को उनके द्वार पर निस्तारण किया जा रहा है। केंद एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनों का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य मंत्री सुशील सैनी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि जिन शिकायतों का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में निस्तारित नहीं हो पाया है उन शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना सुनाश्चित करे। शिविर में ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी, उप ब्लॉक प्रमुख बहादराबाद धर्मेंद्र चौधरी, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए नलिनीत घिल्डियाल,खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल सहित समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

विकास खण्ड नारसन के शिविर में 81 को प्रमाण पत्र दिये

हरिद्वार/रुड़की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ की अध्यक्षता में विकास खंड नारसन के पंचायत भवन लाठरदेवाहुण में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में 81 लोगों को विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए तथा 245 लोगों विभिन्न विभागों की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस शिविर में 2209 लोगों ने प्रतिभाग किया।

बहुउद्देशीय शिविर में कुल 51 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 26 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए। बहुउद्देशीय शिविर को संबोधित करते हुए देशराज कर्णवाल, उपाध्यक्ष, (राज्यमंत्री स्तर) समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा कुल 51 समस्याएं दर्ज कराई गई। पानी की टंकी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, भूमि विवाद, अतिक्रमण, विद्युत विभाग के बिल, जलभराव, चकरोड़, साफ-सफाई तथा राजस्व भूमि से संबंधित समस्याएं प्रमुख रहीं।इनमें से लगभग 21 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा किया गया, जबकि शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु उन्हें संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा नीलकमल शर्मा, खंड विकास अधिकारी नारसन सुभाष सैनी सहित समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

एक नजर

अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत जारी है: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी है लेकिन इस द्विपक्षीय समझौते की तारीख या समय के बारे में तब तक कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जब तक कि बातें पूरी तरह तय न हो जाएं। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने दिसंबर, 2025 के निर्यात-आयात के आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी बाजार में भारत के सामानों पर शुल्क ऊंचा किये जाने के बावजूद अमेरिका को भारत के निर्यात में सालाना आधार पर वृद्धि दिख रही है। उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बारे में एक सवाल पर कहा, ' दोनों पक्ष बातचीत में लगे हुए हैं... और दोनों पक्षों को लगता है कि एक समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौते के लिए दोनों पक्ष बराबर सम्पर्क में हैं। दोनों के बातचीत उच्च स्तर पर बातचीत भी हो रही है। गत दिसंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। दोनों और से वार्ता में शामिल अधिकारियों की टीमें भी वर्चुअली (वीडियो-कांफ्रेंसिंग) के जरिए लंबित विषयों पर बातचीत में लगी है। दोनों पक्षों के समझौते के करीब पहुंचने की बातों का उल्लेख किये जाने पर उन्होंने कहा कि जब तक बात पक्की न हो जाए तो उसे करीब क्या कहा जा सकता है। अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका में ऊंचे शुल्क के बीच ' हम उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान लगा रहे हैं जहां शुल्क कम हैं, या जहां हमारे उद्योग मजबूत है और आपूर्ति श्रृंखला को बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे प्रमुख बाजार में श्रम प्रधान कपड़ा और चमड़ा उद्योग के समक्ष चुनौतियों पर सरकार का ध्यान है। इसी संदर्भ में उन्होंने बाजार विविधीकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। वाणिज्य सचिव ने एक प्रश्न पर कहा कि न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ हुए तीन व्यापार समझौतों पर अमल इसी साल शुरू करने का प्रयास है। 'हम इन समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इनमें कुछ पक्षों (न्यूजीलैंड) को अपनी संसद से अनुमति लेने की आवश्कता हो सकती है। प्रयास है कि हम ये तीन एफटीए इसी साल लागू कर दें। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बीच देश की निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एईजेड) के लिए रियायत और प्रोत्साहन देने की उपयोगिता के बारे में एक सवाल पर कहा कि 'इन क्षेत्रों की ओर से ऐसी मांगें सरकार के ध्यान में हैं और सरकार देख रही है कि वर्तमान दौर में इनके लिए क्या किया जा सकता है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त समझौते के इस माह गणतंत्र दिवस के आसपास हस्ताक्षर होने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर वाणिज्य सचिव ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच 24 में से 22 विषयों को तय कर लिया गया है। उन्होंने कहा, ' दोनों ओर से प्रयास है कि बातचीत के जरिए समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि हम (किसी भी उपयुक्त अवसर पर) उसकी घोषणा की स्थिति में हों।' भारत के तेल आयात के बारे में वाणिज्य सचिव ने कहा कि देश अपने सभी पारंपरिक सप्लायर से खरीद रहा है, लेकिन ज्यादातर तेल पश्चिम एशिया से ही आता है। उन्होंने कहा, 'हम इन दिनों अमेरिका से भी बहुत सारा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका से तेल का आयात बढ़ा है। ईरान से कारोबार करने पर अमेरिका में और ऊंचे शुल्क का सामना होने के जोखिम के बारे में एक सवाल पर श्री अग्रवाल ने कहा, 'ईरान के साथ हमारा व्यापार सीमित है।

जूनापीठाधीश्वर आचार्यश्री से शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट, धर्म-संस्कृति व राष्ट्रहित पर मंथन

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

पंचदशनाम जूना अखाड़ा की आचार्यपीठ हरिहर आश्रम, कनखल स्थित सारस्वत परिसर में जूनापीठाधीश्वर आचार्यमहामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि महाराज से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर आध्यात्मिक संवाद किया।

इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक (खुफिया/सुरक्षा/जेल) उत्तराखण्ड अभिनव कुमार, जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेन्द्र डोभाल, एसपी सिटी अभय सिंह, समाजसेवी सुमित अदलखा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

संवाद के दौरान धर्म, संस्कृति, राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और लोक कल्याण से जुड़े विषयों पर सारगर्भित चर्चा हुई। स्वामी अवधेशानन्द गिरि ने प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में नैतिक मूल्यों, संवेदनशीलता और सेवा भावना को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। अधिकारियों ने आध्यात्मिक चेतना को सुशासन और जनकल्याण से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

बागेश्वर में जल स्रोतों के पुनर्जीवन को वैज्ञानिक व लोकज्ञान का सहारा

पथ प्रवाह, बागेश्वर

जनपद के प्राचीन नौलों, धारों और नदियों के संरक्षण-संवर्धन तथा भू-जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में स्प्रिंग एवं रिवर रीजुविनेशन अथॉरिटी (स्त्रक्र) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने की। उन्होंने जल स्रोतों के पुनर्जीवन को लेकर वैज्ञानिक तकनीकों के साथ-साथ स्थानीय लोकज्ञान को भी योजनाओं में शामिल करने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में जिलाधिकारी ने भागीरथ ऐप पर चिन्हित क्रिटिकल जल स्रोतों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और उनके प्रभावी पुनरुद्धार के निर्देश दिए। उन्होंने गरुड़ गंगा नदी के पुनर्जीवन हेतु विस्तृत, व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि जल स्रोतों के संरक्षण के लिए विस्तृत सर्वे अनिवार्य है, ताकि वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सर्वे में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के साथ-साथ स्थानीय बुजुर्गों और अनुभवी ग्रामीणों के पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वर्षों के अनुभव से प्राप्त जानकारी जल स्रोतों की पहचान और उनके व्यवहार को समझने में सहायक होती है। इससे योजनाएं अधिक प्रभावी और स्थायी बन सकेंगी।

जिलाधिकारी ने स्त्रक्रसे जुड़े सभी विभागों को आपसी समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि आगामी 15 दिनों के भीतर गरुड़ गंगा सहित अन्य महत्वपूर्ण जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

योजना के अंतर्गत कम जलधारा वाले स्रोतों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन के लिए व्यापक पौधरोपण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन संरचनाएं तथा अन्य वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाएंगे, ताकि भविष्य में संभावित पेयजल संकट से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, अभिषेक मेहरा, मुख्य वन अधिकारी दीपक भट्ट, जीआईएस विशेषज्ञ उमेश बिष्ट, रविंद्र सिंह मलड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

5000 मीटर लंबी दौड़ में केदारनाथ के शाहिल ने पाया पहला स्थान

रांसी स्टेडियम पौड़ी में सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ शुरु

पथ प्रवाह, पौड़ी

खेल महाकुंभ-2025 के अंतर्गत आयोजित सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी का गुरुवार को रांसी स्टेडियम, पौड़ी में उत्साहपूर्ण माहौल में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने ट्रॉफी का उद्घाटन करते हुए 800 मीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने खिलाड़ियों से अनुशासन, समर्पण और खेल भावना के साथ मैदान में उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत जरिया बन चुका है। खेल महाकुंभ जैसे आयोजनों से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिलता है।

कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि सांसद

चैम्पियनशिप ट्रॉफी जैसे आयोजन छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचान दिलाते हैं। राज्य सरकार खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

इस चैम्पियनशिप में पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर, श्रीनगर, पौड़ी, चैबटटाखाल, लैन्सडाउन, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग की केदारनाथ व रुद्रप्रयाग, टिहरी की देवप्रयाग व नरेंद्रनगर तथा नैनीताल की रामनगर विधानसभा सहित कुल 11 विधानसभाओं के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।

प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-19 आयुवर्ग के अंतर्गत एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी, रस्साकस्सी, मलखंब, गोली (कंचा), पिट्ठू और मुर्गा झपट जैसी स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। यह प्रतियोगिता 15 से 30 जनवरी 2026 तक चलेगी।

जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 800, द्वितीय को 600 और तृतीय को 400 की धनराशि के साथ प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी के विजेता खिलाड़ी आगे चलकर मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी में प्रतिभाग करेंगे।

प्रतियोगिता के पहले दिन एथलेटिक्स स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया

5000 मीटर दौड़ अंडर-19 बालक वर्ग में केदारनाथ के शाहिल प्रथम, नरेंद्रनगर के हरीश द्वितीय और श्रीनगर के भास्कर रावत तृतीय रहे। 800 मीटर दौड़ अंडर-19 बालक वर्ग में केदारनाथ के आयुष ने पहला स्थान हासिल किया, लैन्सडाउन के आयुष दूसरे और देवप्रयाग के आशीष चौहान तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 600 मीटर दौड़ अंडर-14 बालक वर्ग में लैन्सडाउन के कृष्णा प्रथम, श्रीनगर के प्रकाश नेगी द्वितीय और रुद्रप्रयाग के केशव तृतीय रहे। इसके अलावा गोला फेंक अंडर-19 बालक वर्ग में श्रीनगर के बाबी प्रथम व गौरव द्वितीय और रुद्रप्रयाग के समीर तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ अंडर-14 बालक वर्ग में श्रीनगर के नूर अहमद प्रथम, देवप्रयाग के आशीष द्वितीय और नरेंद्रनगर के अनिरुद्ध तृतीय रहे। गोला फेंक अंडर-14 बालक वर्ग में पौड़ी के आशुतोष राणा प्रथम, देवप्रयाग के सूरजलाल द्वितीय और चैबटटाखाल के सूर्यांश तृतीय रहे। रांसी स्टेडियम में पहले दिन से ही खिलाड़ियों का जोश और प्रतिस्पर्धा देखने लायक रही। आयोजकों के अनुसार आने वाले दिनों में टीम और व्यक्तिगत दोनों स्पर्धाओं में मुकाबले और भी रोमांचक होंगे।

एक नजर

ईरान में बिगड़ती स्थिति के बीच अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी में जुटा भारत

नयी दिल्ली। ईरान में निरंतर बिगड़ती स्थिति और हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबरों के बीच भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने गुरुवार को कहा, 'ईरान में बदलती स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय उन भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी को सुगम बनाने की तैयारी कर रहा है जो स्वदेश लौटना चाहते हैं।

ईरान में अभी लगभग 10,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं जिनमें से करीब 3,000 मेडिकल छात्र हैं, जबकि लगभग 4,000 धार्मिक सेमिनरी के छात्र हैं। इसके अलावा ईरान के तटीय क्षेत्रों में लगभग 2,000 भारतीय मछुआरे भी रहते हैं। इनके अतिरिक्त व्यवसायी, पर्यटक और हर वर्ष ईरान आने वाले हजारों शिया तीर्थयात्री भी शामिल हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को जारी परामर्श में कहा था कि ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, चाहे वे छात्र हों, तीर्थयात्री हों, व्यवसायी हों या पर्यटक, सभी को उपलब्ध परिवहन माध्यमों जिनमें वाणिज्यिक उड़ानें भी शामिल हैं के माध्यम से ईरान छोड़ने की सलाह दी जाती है। दूतावास ने आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किये थे। लोग दूतावास से मोबाइल नम्बर 989128109115, 989128109109, 989128109102 और 989932179359 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास से ई मेल cons.tehran@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भी परामर्श जारी करते हुए कहा था कि ईरान में जारी घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की यात्रा से सख्ती से बचने की सलाह दी जाती है।

मंत्रालय ने इससे भी पहले 5 जनवरी को जारी परामर्श में भारतीय नागरिकों से ईरान की गैर-आवश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया था। मंत्रालय ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से सतर्क रहने और प्रदर्शन प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि निवासी वीजा पर ईरान में रह रहे भारतीय नागरिक, यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। ये परामर्श ईरान में भड़के व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर जारी किए गए हैं, जो पिछले महीने के अंत में ईरानी मुद्रा रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद शुरू हुए थे। ये प्रदर्शन अब देश के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं।

अमेरिका स्थित मानवाधिकार न्यूज एजेंसी (HRANA) के अनुसार देशव्यापी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,500 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय विमान सेवा कंपनियों ने ईरान के ऊपर से गुजरने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी हैं जबकि कई अन्य के मार्गों में बदलाव किया गया है। ईरान द्वारा वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उसके हवाई क्षेत्र को बंद किये जाने के बाद यह फैसला लिया गया है।

उत्तरी कैलिफ़ोर्निया में सड़क हादसे में छह की मौत, एक घायल

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के उत्तरी कैलिफ़ोर्निया में सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गयी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कैलिफ़ोर्निया की पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 10 बजे उत्तरी सैक्रामेंटो घाटी के तेहामा काउंटी में घटित हुई, जहाँ एक पिकअप ट्रक सेंटर लाइन पार करके सामने से आ रही एक बस को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि बस में पाँच यात्री और एक चालक सवार थे।

पोंगल उत्सव के हिस्से के तौर पर तमिलनाडु में तीन दिवसीय जल्लीकट्टू उत्सव शुरू

चेन्नई, 15 जनवरी (वार्ता) दक्षिणी तमिलनाडु में सालाना पोंगल उत्सव से जुड़ा पारंपरिक जल्लीकट्टू कार्यक्रम(बैलों को काबू करना) गुरुवार को मदुरै जिले के अवुनियापुरम में शुरू हुआ। यह कार्यक्रम शुक्रवार को मदुरै के पालामेडु और तमिलनाडु के त्रिची जिले के सूरियूर गांव में होगा और अलंगनल्लूर में 17 जनवरी को होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन करेंगे। इस अवसर पर देश और विदेश से हजारों पर्यटक अलंगनल्लूर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

उत्तरायणी मेले का जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

पथ प्रवाह, बागेश्वर

जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने गुरुवार को ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का स्थलीय निरीक्षण कर मेले में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों, स्वच्छता, सुरक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मेले में आए मेलार्थियों, स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों एवं युवाओं से संवाद कर उन्हें स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक उत्पादों तथा स्वावलंबन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेला जनपद की सांस्कृतिक पहचान होने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष ने सरयू बगड़ में आयोजित काइट फेस्टिवल का भी पतंग उड़कर शुभारंभ

किया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस आयोजन ने मेले के वातावरण को और अधिक जीवंत व आकर्षक बनाया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन उत्तरायणी मेले को अधिक सुव्यवस्थित, जनसहभागितापूर्ण और स्थानीय उत्पादों के लिए प्रभावी मंच बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, पर्यटन अधिकारी प्रदीप कुमार गौतम सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं मेलार्थी उपस्थित रहे।

सुखवन्त सिंह आत्महत्या प्रकरण की जांच तेज, आईजी एसटीएफ की अध्यक्षता में एसआईटी गठित

निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने को 12 पुलिसकर्मियों का गढ़वाल रेंज स्थानांतरण

पथ प्रवाह, देहरादून

जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम पैगा, थाना आईटीआई निवासी सुखवन्त सिंह द्वारा 10/11 जनवरी 2026 की रात्रि काठगोदाम, हल्द्वानी में की गई आत्महत्या के मामले को पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड ने गंभीरता से लिया है। प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय विशेष अन्वेषण दल (स्ढ्ढञ्ज) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ नीलेश आनन्द भरणे करेंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गठित पांच सदस्यीय स्ढ्ढञ्ज में पुलिस अधीक्षक चम्पावत अजय गणपति, क्षेत्राधिकारी टनकपुर वन्दना वर्मा, निरीक्षक दिवान सिंह बिष्ट तथा उपनिरीक्षक मनीष खत्री को शामिल किया गया है। स्ढ्ढञ्ज को आत्महत्या से जुड़े प्रत्येक पहलू की सूक्ष्मता से जांच कर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निष्पक्ष जांच प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से प्रकरण से जुड़े निलंबित तीन उपनिरीक्षक, एक अपर उपनिरीक्षक, एक मुख्य आरक्षी एवं सात आरक्षियों सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से गढ़वाल रेंज के जनपद चमोली एवं रुद्रप्रयाग स्थानांतरित किया गया है। यह कदम विवेचना को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो तथा मृतक द्वारा ई-मेल के माध्यम से की गई शिकायत का भी गंभीरता से संज्ञान लिया है। ई-मेल में स्थानीय व्यक्तियों एवं जनपद ऊधमसिंहनगर पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए

गए आरोपों के तथ्यों का विस्तृत परीक्षण कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण की जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com